

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./134/2022/बाड़मेर
अपीलांत

रेरपोडेंटगण

1. रूपाराम पुत्र महादेवाराम	1. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2. जवानाराम पुत्र महादेवाराम	पंचायत समिति गुड़ामालानी
3. गिरधारीराम पुत्र महादेवाराम	जिला बाड़मेर
4. हुकगाराम पुत्र महादेवाराम	2. नरार पुत्र मादा
जाति कलवी निवासी	3. दुर्गा पुत्र मादा
भावाणियों की ढाणी तहसील	4. धीमा पुत्र मादा
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	5. सुभान पुत्र मदा जाति
	कोटवाल निवासी गुड़ामालानी
	6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला
	बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या
9/2021 बअनवान रूपाराम वगैरह वनाग ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के विरुद्ध पेश हुई।

उपरिथत

1. वकील श्री मोहनलाल विश्‍नोई अपीलान्त की ओर से।
2. राजकीय अगिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेरपोडेंटस संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—10.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेरपोडेंट संख्या 01 से 06 द्वारा
अधीनस्थ अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना-पत्र
पेश कर प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1260/1 रकबा 08.17 बीघा
मौजा बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। आगे यह भी
कथन किया था कि प्रार्थी की खातेदारी खेत के आगे खसरा संख्या 1687 गैर
मुमकिन गोचर का आया हुआ है जिस गोचर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा
परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल की भूमि पर प्रार्थी व उसके बच्चे वगैरह आते जाते हैं
तथा उसका उपयोग करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत/प्रार्थी का
आवेदन विधि विरुद्ध जाकर निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन
आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया,
जिसके विरुद्ध हरतगत अपील पेश की जा रही है।

Amir
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोर्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपरिथत दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस रुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेसपोर्ट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेसपोर्ट/प्रार्थी की गूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर अपीलांटस का आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

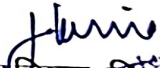
रेसपोर्ट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रतिबंधित भूमि में रास्ता एक ही स्थिति में दिया जा सकता है, अन्य कोई विकल्प नहीं हो। इस प्रकरण में अन्य विकल्प की सही जांच नहीं की गई। अगर पत्रावली को सुनवाई हेतु लौटाई जाती है तो अपीलाधीन आराजी का अन्य कोई उपयोग नहीं करे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि "प्रार्थी द्वारा धारा 251ए के तहत गैर मुमकिन गोचर भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत निजी खातेदारी भूमि में से काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान किये हुए है।" इस संबंध राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 में प्रावधान किया कि "यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे।"

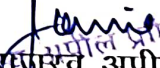
Jain
गजम्ब
अपील प्राधिकारी
बाइमर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्धीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलान्धीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 8/2021 बअनवान हुकगाराग वनाग ग्राम पंचायत गुड़ामालानी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपारत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 में प्रावधान का अनुसरण करते हुए अपीलान्तस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, विस्तृत मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


(प्रतिष्ठा प्रिलानिया)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर